THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI NANDINI SATPATHY) I am greatful to the hon Members who have participated in the debate and made it so lively My colleague Shri Dharam Bir Sinha has already dealt with certain points which were raised during the course of the debate

MR CHAIRMAN You may continue tomorrow

17 31 hrs

HALF AN-HOUR DISCUSSION *Re* DEMANDS BY ALL INDIA KISAN SABHA FOR INSTITUTIONAL CREDIT FOR AGRICULTURAL SECTOR

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) सभापति जी, यह जो आधे घंटे की चर्चा शुरू हुई है वह 25 तारीख के तारांकित प्रश्न 744 के सिलसिले मे है। उसमे अखिल भारतीय किसान सभा ने कुछ मागे सरकार के सामने रखी थी—खासकर किसानो को बैंको का कर्जा और दूसरे किस्म के सरकारी व अर्ध-सरकारी सूत्रो से कर्जा मिले जिससे खेती का विकास हो सके। प्रश्न में उन मागो का जिक्र किया गया है। उसमे यह भी जिक्र किया गया है कि एक माग यह है कि जो बाकी बैंकें है, देसी और विदेशी उनका राष्ट्रीयकरण किया जाये ताकि जो बैंको का राष्ट्रीयकरण हो चुका है उनकी श्रेणी मे और ज्यादा रुपया कर्जा देने के लिए आ जाये। लेकिन इस सवाल के ऊपर सरकार का जवाब बिलकुल चुप है। इसको शीघ्र करने की माग की गई है लेकिन कोई इसका जवाब नही है। हम एक अर्थ यह लगा सकते है कि अभी सरकार की हिम्मत नही है, खासकर विदेशी बैंको का राष्ट्रीयकरण करने की जहा तक माग है कि वह उन विदेशी करोड़पतियो को नाराज करे। लेकिन पिछले चुनाव के बाद आम लोगो ने जो अपनी इच्छा व्यक्त की है उसके बाद हिम्मत होनी चाहिए लेकिन अभी भी इस सरकार की हिम्मत नही हुई है कि खुलकर देश के सामने यह तर्क रखे कि वह कौन सी वजह है जिससे कि, जो बैंकें बाकी रह गई है उनका राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहते सिवाय इसके कि विदेशी करोड़पतियो का रोब और दबदबा इस सरकार पर है और जो पचास करोड से कम की बैंकें इस देश मे हैं उनके मालिको का प्रभाव इस सरकार पर है। कोई और आर्थिक तर्क हो नहीं सकता है।

17 32 hrs

[DR SARADISH ROY *in the Chair*]

इसी तरह मे और मागें गिनाई गई है जैसे इस देश मे अभी भी इस पिछड़ेपन के बावजूद देश की कुल आमदनी का आधा हिस्सा खेती मे आता है और ऐसी स्थिति मे हम बैंको से आधा कर्जा खेती मे जाना चाहिए। हम नही कह सकते कि अभी एक चौथाई कर्जा भी खेती के लिए जाता हो। जहा तक बैंको का सवाल है उनका तो दस प्रतिशत भी नही जाता है ऐसी हालत मे जो माग है कि 50 प्रतिशत कर्जा खेती के लिए जाये उसपर सरकार का जवाब चुप है। जो भी थोडा सा कर्जा खेती मे गया है उसका एक बडा हिस्सा, जो चाय बागान के मालिक है या जिन्होने चोरी का रुपया काले बाजार का रुपया लेकर बडे बडे फार्म बना लिए हैं उन्ही लोगो ने ले लिया है और यह सरकार हिसाब लगा देती है कि खेती के लिए इतना रुपया दिया गया है। इसलिए अखिल भारतीय किसान सभा ने माँग की है जिसका कि उसमें जिक्र है कि एक परिवार को ज्यादा रुपया खेती के लिए न दिया जाये। दूसरा सवाल यह भी किया था कि कितने ऐसे परिवार हैं जिनको दस हजार से ज्यादा खेती के लिए कर्जा दिया गया गया है तो उसका जवाब दिया गया कि अभी मालूम नही

[श्री भोगेन्द्र झा]

है, सूचना इकट्ठी की जा रही है। यह ठीक है कि मालूम नहीं है लेकिन जरूरत है कि सरकार एक हदबन्दी तय करे कि इससे ज्यादा रुपया किसी एक परिवार को खेती के नाम पर नहीं दिया जायेगा वरना कुछ परिवारों को 25 लाख दे देंगे और कह यह देंगे कि खेती के नाम पर इतना रुपया सारे देश में दिया गया। तो इस सवाल पर भी सरकार का जवाब मौन है। इसी प्रकार से उसमें एक मांग यह भी थी कि अपेक्स बैंके और सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक को हटा दिया जाये और जो राष्ट्रीयकृत बैंकें है उन्ही के माध्यम से कोआपरेटिव सोसायटीज़ के सदस्यों को सीधे सस्ते दर पर कर्जा मिले। इसके बारे में भी सरकार का कोई जवाब नही है।

इसी प्रकार से पश्चिम कोसी नहर, गंडक नहर, जो राजस्थान नहर जैसी जो बड़ी योजनायें है, पैसे के अभाव में बहुत धीमी रफ्तार मे उनका काम हो रहा है। और नतीजा होता है कृषि उत्पादन में कमी और विदेशी मुद्रा का व्यय, विदेशी खाद्यान्न का मंगाया जाना, कारखानों के लिये कच्चे माल की कमी। ऐसी स्थिति में इन बैंकों का पैसा क्यों न लगाया जाय, खासतौर से महत्वपूर्ण सिंचाई योजनाओं मे ताकि पैसे के अभाव में काम अधूरे न रहें। उस सवाल का जिक्र कर दिया गया अगर उसका जवाब नही दिया गया। एक मांग रखी गयी थी, पिछले साल 19 जुलाई को बैंक के अफ़सरों की एक बैठक वित्त मंत्री महोदय ने बुलायी थी जिसमे तय हुआ था कि डिफ़रेंशियल रेट आफ़ इंटरेस्ट हम चालू करेंगे। यानी जो कम जमीन वाले लोग हैं, किसान हैं खास कर जिन्हें सरकार ने मार्जिनल फ़ार्मर्स कहा है, दो एकड़ से पांच एकड़ के जो किसान हैं, उन लोगों को हम कम सूद की दर पर पैसा देंगे और ज्यादा जमीन वाले किसानों के लिए सूद की वही दर रहेगी जो कि है। इस फैसले को एक साल होने आ रहा है पर अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ है और न कहीं सरकार का ऐलान है। इस जवाब में कहा गया है कि उस पर हम कुछ अमल करने जा रहे हैं। तो ऐलान के भरोसे आप वोट ले सकते हैं लेकिन कृषि की हालत नहीं बदल सकती है, देश की हालत नहीं सुधर सकती है।

वैसे ही देश में अभी एक भी गांव नहीं है, एक भी बड़ा शहर नहीं है जहां गैर कानूनी सूदखोरी खुले आम नही चल रही है, जहां महाजनों का तबका खुले आम कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा हो। अखबार करोड़पतियों के हैं इसलिये वे इस तरह की गैर कानूनी सूदखोरी के बारे मे चुप हैं। और अगर जनता एक गैरकानूनी सूदखोरी के लिए कहीं आवाजें उठाती है, या आन्दोलन करती है तो उस पर कानून भंग का जुर्म लगाया जाता है और नक्सलाइट कह कर हगामा किया जाता है। मैं चाहूंगा कि इस प्रकार की सूदखोरी के खिलाफ़ कानून सख्ती से लागू किया जाय जिस से महाजन लोग गैरकानूनी सूदखोरी न करने पायें। उनको जेल में बन्द किया जाय, या नज़रबन्दी कानून के अंदर नज़रबंद किया जाय। लेकिन इस सवाल पर इनका जवाब बिल्कुल चुप है। मैं जानना चाहूंगा कि इन सवालों पर सरकार को क्या कहना है? क्या गैरकानूनी सूदखोरी को बन्द करने के लिये आप कोई कदम उठाने जा रहे हैं। आज दिल्ली में 75 फ़ीसदी सूद लेते है और हर माननीय सदस्य के क्षेत्र में ऐसा होता है, और ऐसा करने वाले नक्सलाइट नही बल्कि वे शिक्षित लोग हैं जिन्हें समाज में, शासन में प्रतिष्ठा है, मिनिस्टर और एम. पीज़. के अगल बगल बैठते है। तो जो पैसे वाला कानून तोड़ने वालों का तबका है। इनके खिलाफ़ सरकार का कानून चलेगा कि नहीं ? या लोगों को मजबूर होकर आन्दोलन

करने पर मजबूर करेंगे तभी कानून का उल्लंघन रोका जायेगा ? इसका भी कोई जवाब सरकार की ओर से नही आया है। इन्होंने गोलमोल जवाब दिया है कि कुल तरक्की काफी बड़े पैमाने पर हुई है, और जो पिछड़े इलाके हैं उन का हमने काफी ख्याल रखा है कि वहां बैंक की शाखायें खोली जावें। अखिल भारतीय किसान सभा ने माग रखी थी कि 25,000 की आबादी पर एक बैंक की शाखा खोली जाय। इसका भी कोई जवाब नही आया। 2 जुलाई के अतारांकित प्रश्न संख्या 3763 के जवाब मे इन्होने कुछ नाम गिनाये है बिहार और देश के बारे मे। देश भर मे एक बैंक की शाखा पर 47,000 की आबादी पडती है। बिहार मे एक बैंक की शाखा पर 1 लाख 35 हजार आबादी पड़ती है। बिहार ही ऐसा नही होगा, कुछ और राज्य भी होगे, लेकिन सारे देश के लिये इनका ऐवरेज है 47,000 की आबादी पर एक बैंक की शाखा। जब कि बिहार के लिये 1 लाख 35 हजार आबादी है। तो क्या आप बिहार या ऐसे ही जो और राज्यो के पिछड़े इलाके है, उनके लिये कुछ विशेष कार्यक्रम अपना रहे हैं जिस मे इस वित्त वर्ष का अन्त होते होते अखिल भारतीय स्तर पर आप उन्हे ले आयें ? इस बारे से जवाब चुप है। उत्तर बिहार के बारे मे इनके 2 जुलाई के जवाब से उद्धरण दे रहा हू जिसमे बताया है कि दरभंगा मे 2 लाख 26 हजार की आबादी पर एक शाखा है। तो पूरे देश के लिए आपका ऐवरेज 47,000 की आबादी पर एक शाखा है, जब कि बिहार के लिये 1लाख 35 हजार की आबादी पर एक शाखा है और दरभगा के लिये 2 लाख 29 हजार की आबादी पर एक शाखा है। यह 31 मार्च, 1971 के आधार पर इनका जवाब है।

सारण के लिए 2 लाख 62 हजार पर एक बैंक की शाखा है, मुजफ्फरपुर के लिए 1 लाख 84 हजार पर एक बैंक की शाखा है। इसी तरह से उत्तर बिहार के जिलों के लिए है। तो ऐसी स्थिति मे क्या आप आशा करते हैं कि जिन इलाको को आपने जिस तरह से पिछड़ा छोडा है और आगे भी पिछड़ा बनाने की योजना है जो कि इनके उसी जवाब से स्पष्ट है कि विशेष प्रयत्न करने की योजना नही है तो क्या आप चाहते हैं तेलगाना की तरह से लोग आगे बढ़ें या तेलगाना वाले अगर धीमे भी हो जाएं तो दूसरे इलाको के लोग क्षेत्रीय स्थापन के लिए कदम उठाये।...(व्यवधान)

वित्त मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) तेलगाना तो खत्म हो गया।

श्री भोगेन्द्र झा : दूसरे इलाके के लोग जब तेलगाना बनने के लिये मजबूर करेंगे, तब सुनेंगे, तभी आप ध्यान देंगे। इसलिए अखिल भारतीय किसान सभा की यह खास करके माग थी कि देश भर मे कम से कम एक प्रखड विकास इलाके के अन्दर एक बैंक की शाखा जरूर हो। आम तौर से प्रखड एक लाख, डेढ लाख या 75 हजार की आबादी पर है। कम मे कम एक बैंक की शाखा एक प्रखंड मे हो जाय। जिसमे पैसा जमा भी हो सके और कर्ज की सहूलियत हो जाय। इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक हर एक प्रखड मे कम से कम एक बैंक की शाखा हो वहा भी ये चुप हैं। इन सवालो का जवाब मैं चाहता हू आज भी ये दें क्योकि अखिल भारतीय किसान सभा ने यह तय किया है कि अगर इन सवालो पर सरकार कोई ठोस कार्यक्रम चलाने का सतोषजनक जवाब नही देती तो 14, 15 और 16 जुलाई से बैंको का शान्तिपूर्ण घेराव होगा क्योकि किसान घूस देकर बैंकों को खरीद नही सकते चार व्यापारी खरीद सकते हैं। मेरे एक सवाल के बारे में सरकार ने जवाब दिया है कि करोड़पतियो को बैंक कर्जा देना बन्द नही करेंगे। ये बातें समाजवाद की करते

[श्री भोगेन्द्र झा]

हैं, लेकिन, सभापति जी, मैं आपके जरिये से कहना चाहता हू कि ये ईमानदारी से कह दें कि अभी उसी हालत मे पूजीवाद को ये बढने देना या रहने देना बरदाश्त करेंगे। यह कोई सिद्धान्तत अव्यावहारिक बात नही होगी लेकिन ईमानदारी से कह दें कि जनता का पैसा पूजी-पतियो को नही देंगे। उनसे कह देंगे कि अपने पैसे से पूजीवाद बढाओ और जो जनता पैसा दिया है उस पैसे को वापस दे दो। लाइफ इश्योरेंस का जो पैसा है, बैंक का है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन का जो पैसा है, जो सारे देश का पैसा है चाहे वह जीवन बीमा निगम का हो, विभिन्न सरकारी मदो का हो, वह करोडपतियो को दे रहे हैं और चर्चा हो रही है समाजवाद की, समाजवाद लाने की। इतना बडा ढकोसला हो रहा है खुले आम देश के सामने। इसीलिए मैं कहता हू कि अपने पैसे से पूजीपति अपनी पूजी बढाये कारखाने बढाये। जनता के पैसे से हम सरकारी कारखाने चलायेंगे, उनको नही देंगे। इतना भी यह कर दें तो बहुत बडा कदम है। लेकिन यह ईमानदारी नही है जो ये बोल रहे है। इसी दृष्टि से मैं कह रहा हू कि 14 15, 16 जुलाई को घेराव होगा, ये गिरफ्तारिया करेंगे, लाठिया चलायेंगे। अगर इसे यह टालना चाहते हैं तो सतोषजनक जवाब दें जिससे कि देश आगे बढे कृषि आगे बढे, और जिस उद्देश्य से बैंको का राष्ट्रीयकरण हुआ इस उद्देश्य की पूर्ति की तरफ हम कदम बढा सकें और सारा देश मिलकर आगे बढ सके।

श्री कमल मिश्र मधुकर (केसरिया) सभापति जी यह जो प्रश्न उठाया गया है और जो मागे उठाई है इन बातो का समर्थन करते हुए मैं मत्री महोदय से जानना चाहूगा क्योंकि मुझे अनुभव है कि बिहार के पिछडे इलाको की स्थिति क्या है और उनमे चम्पारन जिला भी है जो बहुत पिछडा इलाका है और वहाँ हमने देखा कि स्टेट बैंक की शाखा के जो काम करते है उन के बडे किसानो और बडे जमींदार लोगो को ही ऋण लेने मे सुविधाए दी जाती है और जो मझोले किसान लोग होते है उन लोगों के साथ घुसखोरी और तरह तरह की अडंगेबाजी होती है। ऐसा कहा गया है कि स्टेट बैंक की जो शाखा है मोतिहारी मे उसके खिलाफ हजारो शिकायतें आई है। इसलिए मै जानना चाहता हू कि क्या आप ऐसी व्यवस्था करने जा रहे है कि कम से कम हर ब्लाक मे एक बैंक की शाखा खुल जाए और साथ ही साथ ऐसा करप्शन जिसके जरिये से मझोले किसानो को ऋण लेने मे असुविधा जो हो रही है उसको दूर करने के लिए आप ठोस कदम उठायें। कौन सा आपने उपाय सोचा है। आज उनको कोई फायदा नही हो रहा है। आपने कहा है कि कोई नई स्कीम आप इसके लिए लाने जा रहे है। मै जानना चाहता हू कि नई तजवीज आपके पास क्या है, इसको आप बतायें।

श्री रामावतार शास्त्री यह बहस बहुत महत्वपूर्ण है। मत्री महोदय ने जिस प्रश्न का उत्तर दिया है वह साफ नही है। जो बातें पूछी गई है उन्ही के सिलसिले मे सरकार ने कहा है कि इससे देहातो मे एम्प्लायमेंट बढाने मे मदद मिलेगी। मै जानना चाहता हू कि इस दिशा मे सरकार को कहा तक सफलता मिली है और राज्यवार इसकी स्थिति क्या है।

किसान सभा ने माग की है कि दो महीने के अन्दर अन्दर जो एप्लीकेशज लोन के लिए पडी हुई हैं उनका फैसला हो जाना चाहिये। इसका जवाब उस प्रश्न मे नही दिया गया है। समय को कम करने के सिलसिले मे सरकार ने कोई कार्रवाई की है या नहीं की है और अगर की है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इन्होंने कहा है कि बहुत बड़ी संख्या में बैंकों की शाखायें खोली गई हैं। यह बहुत खेद की बात है। जब से बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है तब से पिछले दो सालों में आपने प्रत्येक राज्य में कितनी शाखायें खोली हैं और उन में से कितनी शाखायें देहातों में खोली हैं, यह मैं आप से जानना चाहता हूं। यह प्रश्न देहातों से सम्बन्धित है।

धनी किसानों को तो आप कर्ज देते ही हैं। लेकिन आपने कहा है कि हम छोटे किसानों को भी कर्ज देंगे। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले दो बरस के अन्दर आपने कितने छोटे किसानों को कर्ज दिये हैं। अगर इसका ब्यौरा राज्यवार आप के पास है तो वह क्या है ? इस से पता चल सकेगा कि आपने छोटे किसानों को कितना धन दिया है।

अगर आपने सन्तोषजनक जवाब दिया तब तब तो अंदाज़ हो सकेगा कि आप कुछ कर रहे हैं, वर्ना क्या होगा, यह आप जानते ही हैं।

SHRI C. K. CHANDRAPPAN (Tellicherry): While nationalising the banks government stated that their two main objectives were, firstly, to create employment opportunities among the people and, secondly, provide credit to those sectors which were so far neglected. While answering a question in the House on 18.6.71 the Finance Minister, Shri Chavan, stated that the banks are not keeping a separate account of the credit given to the small farmers. The credit which the nationalised banks give to the agrarian sector has definitely increased. While in 1969 it was Rs. 26 96 crores, in 1970 it came to Rs. 98.47 crores and in 1971 it rose further to Rs. 194 7 crores. But, unfortunately, the government is not keeping any separate account as the the people to whom the credit goes. It is quite likely that the credit is going still to the big farmers, the big capitalist interests in the agrarian sector. I would like to know whether the hon. Minister will make some definite arrangements in the nationalised banks to see to whom the credit is going and particularly how much is going to the small farmers. Secondly, is the same old criteria being maintained of movable or immovable property as guarantee for credit? In that case, how can the poor landless peasants take advantage of the credit offered by the nationalised banks? So, will the government think in terms of changing the present conditions for grant of credit?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. R. GANESH): Mr. Chairman, Sir, since the discussion has been raised on the entire working of the banking industry you will agree with me it will not be possible, within the time at my disposal, to answer all the points that the hon. Members have raised because they have touched on the entire working of the banking industry. So, I shall confine my answer to some of the specific points that they raised. Firstly, the hon'ble Member raising this discussion seems to be under a misconception that all the evils of our society are to be remedied just by the nationalisation of banks. We have quite a lot of problems in our society which have got to be solved and there are various strategies which the Government is using to solve these problems-to remove the imbalance, to remove disparities in income and to control the monopolies. Bank nationalisation happens to be one of these strategies. In answer to the hon'ble Member's questions-and he has asked extensively from the Ministry questions on various aspects of the bank credit—we have supplied as much information as could be supplied. We have not hidden any information. Those informations that were not available we have taken time to supply. The objective of bank nationalisation, firstly, was to help the national economy; secondly, to help the hitherto neglected sectors of our economy which are now called as neglected priority sector; and, thirdly, to remove the imbalance that is there in our economic life. When you judge the results of bank nationalisation, you have to keep all these factors in view because whatever deposits are there, whatever amount is there at the disposals of the banks, have got to be used in furtherance of these three or four factors for which bank nationalisation has been done.

Having said this, I would now refer to some of the specific points that the hon'ble

[Shri R. K. Ganesh]

Member has raised. His first point was about nationalisation of foreign banks. This question has been time and again answered on the floor of the House that, at present moment, the Government does not consider it desirable to nationalise foreign banks because the foreign banks play a specific role in the entire national economy. There is some expertise connected with the foreign banks. At the present moment, we have nationalised 14 commercial banks and, at the present moment, it is considered desirable to allow these foreign banks to play the specific expertise role that they are playing.

As I said earlier, this Government is not afraid of foreign interests or any other interest. When the Government considers that the time has become ripe for nationalising foreign banks, the Government will come before the Parliament and will not hesitate to do that. At the moment, as has been stated time and again, the Government does not consider it necessary and desirable to do it because of the factors that I have indicated.

He also raised another point that 50 per cent of the institutional credit should be given to the agricultural sector. I think, the agricultural sector as a whole has been a neglected one before nationalisation of banks. After nationalisation of banks, the agricultural sector has been considered as a priority sector and more and more credit is being channelised to the agricultural sector.

The facts have been supplied to the Hon. Member from time to time. If he wants me once again to re-state these facts, I can do that. As on 30th June, 1969, there were 1,76,636 borrowal accounts with outstandings at Rs. 160 54 crores, that is just on the eve of bank nationalisation, After nationalisation, these borrowal accounts have increased to more than 8 lakhs and the outstanding are Rs. 344 05 crores as on 31st December, 1970. Therefore, the share agricultural sector has risen from 5.3 per cent to 9.2 to 10 per cent.

Then, the former criteria of secruity-oriented lending have been replaced by viability of the project. These guidelines have been given. The Credit Guarantee Corporation has come into existence from 1st April, 1971 and from this also greater flow of credit will go to the agricultural sector. Apart from this, the banks, the State Trading Corporation and other institutions which directly deal with the agricultural sector are also financing.

The magnitude of the task as far as agricultural sector is concerned is so formidable that it is not possible for these nationalised banks during the short period of the nationalisation to cover the entire agricultural sector But a significant beginning has been made. Here, I am putting forward these facts not with any apology because a significant beginning, a significant dent, has been made in a sector which was hitherto neglected by the commercial banks. It is the intention of this Ministry to see that more and more credit is given to the agricultural sector. These are the guidelines that were given be the Finance Ministry to the Custodian of nationalised banks.

I concede the point that the Hon. Member has raised about the credit which has gone to the agricultural sector as to which sections of agricultural sector it has gone. This is a very pertinent point raised by the Hon. Member. We have tried to examine that also. I can convince the Hon. Member that a very substantial portion of the credit has gone to small borrawers between Rs. 2000 to Rs. 3000. I have checked it. I am not saying here that all credit has gone to them; That is a question which has got to be investigated and the Ministry itself is busy in investigating that out of whether credit has gone to the agricultural sector, which sections it has gone to most. We are also interested so much as the Hon. Member is interested in seeing that the credit goes to the priority sector and to those sections of agriculturists who are marginal farmers and other small peasants who actually need credit. This is a very serious study which the Ministry is trying to makes.

As far as our statistics are concerned, we shall make them uptodate so that we know that credit which is channelised to the agricultural sector and which will go on increasing as the time proceeds goes in substantial portion to those sections of

agriculturists who really need credit and who have been all this time denied credit.

18 hrs.

The other point that the Kisan Sabha leader has raised is about the opening of a branch for every 25.000 of the population. As far as the opening of branches is concerned, I think a subtantial number of branches has been opened. Figures have been supplied to hon. Members. If they still want some figures, I can give them...... (*Interruptions*). It is not a question of conceding this principle. The criteria have been laid down by the Reserve Bank that, in cases of banked centres, there will be one bank for every 10 000 of the population. This criterion is relaxable depending upon the commercial and industrial importance of the centre. In un-banked centres, banks are permitted to open offices irrespective of the population of the centre. In order to induce banks, the Reserve Bank have laid down the ratio of 2:1 in case of banks which have their offices in rural and semi-urban areas and 3:1 in other cases. It is not a question of opening a branch for every 25,000 of the population but it is a question of opening branches in rural and semi-urban areas and a large number of banks have been set up. This is quite a substantial figure.

SHRI BHOGENDRA JHA : At least there should be a bank in each Development Block of the country.

SHRI K. R. GANESH : It can be more than one as the hon. Member says. On 30th June 1969, there 8254 branches spread over the length and breadth of the country. On 31st March 1971 11,540 branches have come into existence and most of these branches, at least 60 to 70 per cent of them, have been opened in rural areas.

As far as branch expansion is concerned, practically it has taken place at a very rapid rate. Actually, there have been criticisms that some of these branches have been opened in a great hurry. The hon. Member's own friends, in the meeting the Ministry had with the employers and the employees and at the meeting the Finance Minister had with the Custodians, have raised this question that target-oriented expansion of branches has not been fruitful and has not served the purpose for which they have been opened.

SHRI BHOGENDRA JHA : Why don't you go into rural areas ?

SHRI K. R. GANESH : You can help us a lot in that. The All India Bank Employees' Association is a powerful trade union, a militant trade union and is a very conscious and organised trade union and if they can use their authority and influence, I think this problem can be solved....(*Interruptions*). We opened more than 60% of the branches......

SHRI BHOGENDRA JHA : At least in Bihar, no Development Block has got a branch.

SHRI K. R. GANESH : It is true. Figures have been supplied to hon. Members. The figures of Bihar compared to the all-India figure are certainly less. More and more branches to be opened. The lead bank scheme is there. The lead bank will investigate in each area the banking requirements of that area and, according to that programme, the branches will be opened. I can assure the hon. Member that as the opening of branches in rural, semi-urban and unbanked areas is concerned, the Government is determined that, within the shortest possible time, branches should be opened so that credit is available to the needy and priority sectors and also that the banking habit in those sectors increases.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Everybody has got the banking habit but the question is that there is no money.

SHRI K. R GANESH : There is money in the agricultural sector. At least if bank open, we can draw out deposits from that section of the agricultural society which has been some affluence during the last 10-15 years.

The next point raised was whether a limit of 2 months could be prescribed for disposal of applications It is not possible to rigidly apply the limit. It has been found that when records are complete, when all the formalities have been completed, then it takes about two to four weeks, depending upon the nature of the loan, for the competent authority to sanction the same.

SHRI BHOGENDRA JHA : Why cannot you prescribe ?

SHRI K. R. GANESH : I don't understand the rationale of fixing this limit of 2 months.

SHRI BHOGENDRA JHA : There is corruption based on this which flourishes because of this.

SHRI K. R. GANESH : There is no rationale in fixing this period. The point is that there should be expeditious disposal of loan applications. It can be even one or two weeks. Therefore, why should the hon. Member want it to be limited to 2 months ?

SHRI BHOGENDRA JHA : One who offers bribe gets in 3 days. That is, without you. Your limit is needed only for those who are not offering bribes.

SHRI K. R. GANESH : The hon. Member should realise, even if you fix 2 months limit, if corruption is to be there, you cannot check it.

SHRI BHOGENDRA JHA : It is a means of corruption.

SHRI K. R. GANESH : I am very sincerely arguing with you that this 2 months limit hardly serves the purpose you want. The point is that there should be expeditious disposal of applications and that the banks should be in a position to help the smaller borrowers, without any corruption coming into being. There is no difference as far as this ideal is concerned. The question is, how can we implement it ?

How is this to be implemented ? It is not only for the Government, the Minister and the Banks, but the Hon. Member can also help us, because, whenever a case is brought up, either of delay or of corruption or of refusal, we certainly go into it and bring it to the notice of the banks and take action. That is because we are also interested in making the Bank Nationalisation a success.

SHRI BHOGENDRA JHA : So are we.

SHRI K. R. GANESH : The hon. Member is interested ; we are also interested we will make our efforts so that the enemies of Bank Nationalisation may not succeed, so that Bank Nationalisation which has brought a trememdous upsurge in this country succeeds in the objectives for which Bank Nationalisation has been done.

I think I have tried to answer most of the specific points raised by Hon. Members.

SHRI C. K. CHANDRAPPAN : I want to know whether you will have in the Banks a section to clearly see how much money you have given to small farmers. At the moment you don't have this. You give a consolidated amount. There is a danger. The money might go into some hands which you don't want also. So, I want to know whether you will have a section in the Nationalised Banks to see to this.

SHRI K. R. GANESH : I should submit this, that thousands and thousands of branches are spread all over the length and breadth of this country. It is a formidable task to have this particular check. We are interested ourselves in knowing as I indicated earlier whether credit which is going to the agricultural sector goes to the needy and marginal section of the persantry or to the affluent section. It is really a question of working out what should be the method of finding out this particular statistics and I agree with the Hon. Member that some method should be worked out to find out to what section of the agricultural community this credit has gone. I agree, it is a very important matter.

I can take the hon. Member, through you, Mr. Chairman, into confidence. In whichever bank I have gone, I did this. I have asked them, please give me a break up of the credit that has gone to the agricultura sector." On the basis of my own investigations, I have found that, in quite a lc of banks, where I have had opportunity t investigate, much of the credit has gone t borrowal accounts, which are on an averag about Rs 2.000 to Rs. 3000.

SHRI BHOGENDRA JHA : What h happened to differential rates of interest ?

SHRI K. R. GANESH : A commit was set up to go into this matter and it I

made certain recommendations, and they are under the examination and consideration of the Finance Ministry.

I think I have answered most of the specific points raised by bon. Members. In conclusion, I would only say that, during the last two years, in terms of branch expansion, in terms of channelising credit within the present limits, in terms of channelising credit to the agricultural sector, to small traders, to transport operators and to self-employed persons, in terms of helping those neglected sectors, in terms of changing the criteria of giving credit, the banks have done a good job.

SHRI BHOGENDRA JHA: What about financing of the Rajasthan, Gandak and Kosi projects ?

SHRI K. R. GANESH: I do not say that the banks have succeeded completely. It is a formidable task. It is a task which requires the co-operation of hon. Members and requires the co-operation of employees; the employees are giving their co-operation, and there is no doubt about it; it requires changes in the habits and it requires all these things. But I must say this in all sincerity, because I have gone with some interest into the various questions that have come up and have discussed with the employees, that I should say that the record of the banks, in terms of giving credit, in terms of bringing about an orientation, not a complete orientation, I concede, has been good.

18.12 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, July 8, 1971/Asadha 17, 1893 (Saka).